



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16122020-223726
CG-DL-E-16122020-223726

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 635]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 16, 2020/अग्राहायण 25, 1942

No. 635]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 16, 2020/AGRAHAYANA 25, 1942

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 दिसंबर, 2020

सा.का.नि. 767(अ).—केंद्रीय सरकार, विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) की धारा 13 की उप-धारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार की सहमति से अंतर-राज्यिक व्यापार और वाणिज्य के संबंध में, उक्त अधिनियम की धारा 18, धारा 27, धारा 28, धारा 29, धारा 30, धारा 33, धारा 34, धारा 35 और धारा 36 के उपबंधों और विधिक माप विज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 2011 के नियम 32 से सम्बंधित निदेशक द्वारा प्रयोक्तव्य सभी शक्तियाँ बिहार राज्य क्षेत्र के नियंत्रक विधिक माप विज्ञान को इस शर्त के अधीन प्रत्यायोजित करती है कि उक्त उपबंधों के अधीन की गई कार्रवाई की तिमाही रिपोर्ट जिसमें दर्ज किए गए, शमनीय, अभियोजित और दोषसिद्ध मामलों की संख्या सम्मिलित है, निदेशक को भेजी जाएगी।

[फा. सं. डब्ल्यू.एम.-9(21)/2020]

अनुपम मिश्रा सयुक्त सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION**(Department of Consumer Affairs)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th December, 2020

G.S.R. 767(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 13 of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010), the Central Government, with the consent of the State Government, hereby delegates all powers exercisable by the Director in relation to inter-State trade and commerce relating to the provisions of sections 18, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35 and 36 of the said Act and under rule 32 of the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011 to the Controller of Legal Metrology in the State of Bihar subject to the condition that a quarterly report of the action taken under the said provisions including the number of cases booked, compounded, prosecuted and convicted shall be sent to the Director.

[F. No. WM-9(21)/2020]

ANUPAM MISHRA Jt. Secy.